



कृषि विद्यापार में सुगमता की जाँच के लिये नया सूचकांक (New index to check ease of doing agri-business)

चरण में क्यों?

केंद्र सरकार अगले वर्ष की शुरुआत में कृषि विद्यापार में सुगमता हेतु एक नया सूचकांक शुरू करना चाहती है। यह सूचकांक राज्यों को कृषि में उनके निवेश, उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी और जोखिमि शमन उपायों के साथ ही साथ अन्य सुधारों के आधार पर रैंक प्रदान करेगा।

प्रमुख बातें

- राज्यों को जल्द ही कृषि विद्यापार को प्रोत्साहित करने में वशीष्टकर विप्रिण, भूमि और शासन में सुधारों के संबंध में उनके प्रदर्शन के आधार पर कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिये अतिरिक्त धनराशभिलिने की शुरुआत हो सकती है।
- सूचकांक के लिये जारी किये गए हालायि अवधारणा नोट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय वभिन्न प्रमुख योजनाओं में उपलब्ध फ्लेक्सी फंडों से आवंटन के साथ प्रदर्शन को जोड़कर उच्च निषिपादति राज्यों को [पूर्ण और वृद्धशील दोनों शर्तों में] पुरस्कृत करने पर विचार कर सकता है।
- नीतिआयोग पहले से ही एक कृषि विप्रिण और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है, जो इन सुधारों के कार्यान्वयन पर राज्यों को रेटिंग प्रदान करता है। वर्ष 2016 में उस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में महाराष्ट्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, इसके बाद गुजरात का स्थान था।
- इस प्रस्तावित सूचकांक का विस्तार अत्यंत व्यापक है, लेकिनि मुख्य केंद्रण अभी भी सुधारों पर है। विप्रिण सुधार (25%) तथा शासन और भूमि सुधार (20%) इस सूचकांक की मूल्यांकन प्रणाली के मापदंडों के वज्रन का लगभग आधा हसिसा रखते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- अन्य मापदंडों के तहत, राज्यों का मूल्यांकन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण तथा जैविकि कृषि और सूक्ष्म सचिवाई को प्रोत्साहित करके कृषि आगामों (20% भारांश) की लागत में कमी करने में राज्यों को मली सफलता के आधार पर किया जाएगा।
- फसल और पशुधन बीमा जैसे जोखिमि शमन उपायों का भारांश 15% होगा, जबकि कृषि में उत्पादकता तथा निवेश में वृद्धि इन दोनों का भारांश 10-10% होगा।

प्रक्रिया उन्मुख मापदंड

- अवधारणा नोट के अनुसार, ये मापदंड प्रक्रिया उन्मुख हैं, और जब नए सुधार या पहल प्रस्तावित किये जाते हैं, तब ये विकसित होते हैं।
- चूंकि कृषि एक राज्य विषय है, अतः केंद्र द्वारा प्रस्तावित नीतियों और सुधार पहलों की सफलता राज्यों द्वारा कार्यान्वयन पर निर्भर है।
- इस नोट के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये किसिकार के सुधार एजेंडे को सभी राज्य सरकारों द्वारा वांछति गतिसे लागू किया गया है, राज्यों के बीच एक प्रतिसिपरद्धी भावना विकसित करने की आवश्यकता है।
- 2022 तक किसिनों की आय को दोगुना करने की रणनीतियों की सफिराशि करने के लिये गठति समतिने भी यह सुझाव दिया था कि राज्यों को उनके सुधार और शासन रकिंरड के आधार पर रैंक प्रदान किया जाना चाहिये।
- यह अवधारणा नोट 15 नवंबर तक सार्वजनिक और हितिधारकों की प्रतिक्रिया के लिये उपलब्ध है, जिसके बाद महीने के अंत तक कार्यान्वयन दशानिर्देश तैयार किया जाएगे।
- अवधारणा नोट की समय-सारणी के अनुसार, राज्य के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड वर्ष के अंत तक विकसित किया जाएगा और सूचकांक को जारी करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला जनवरी 2019 में आयोजित की जाएगी।